SHRI R. VELU: It is unfair on his part. *(Interruptions)*... Please, withdraw your statement. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI R. VELU: He should withdraw this statement.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: No, no.

SHRI R. VELU: You cannot make an allegation against a Minister.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: No, no. I know employees are being transferred from one area to another forcibly. So many complaints are there. I stand by what I have said.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: I can establish the truth of the point that I have made in the House.

MR. CHAIRMAN: Question No. 423.

Approval for registration of products of M/s Dow Chemicals

*423. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken cognizance of the report of disclosure made in the 13th February, 2007 report of the US Securities Exchange Commission (SEC) about the confession of M/s Dow Chemicals of having bribed Government officials in India some years ago for securing registration/approvals of their products;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted on the basis thereof;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Yes, Sir. Based on the findings of the preliminary enquiry, the Ministry has decided to refer the case to the Central Bureau of Investigations for further action.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैंने सवाल किया था कि जो इसकी एक इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उसका आऊटकम क्या हुआ? मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया है कि हमने सीबीआई इन्क्वायरी के लिए निर्णय लिया है। महोदय, सवाल यह था कि बहुत लोग भोपाल गैस त्रासदी को भूल चुके हैं और यह डॉव कैमिकल्स वही फैक्टरी है, जिसने यूनियन कार्बाइड को खरीदा है। यूनियन कार्बाइड खरीदने के बाद, खासकर के जो सेंट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड है, सीआईबी, जो भारत में कैमिकल्स बनाने की परमिशन देता है, युनाइटेड स्टेट्स ने डॉव कैमिकल्स को 3 लाख 25 हजार डॉलर का फाइन किया है कि उन्होंने कैमिकल्स बनाने के लिए वर्ष 1996 से लेकर 2001 के बीच में यहा सीआईबी के आफिशियल्स को करीब 2 लाख डॉलर ब्राइब देकर वह लाइसेंस लिया है। आपने यह जो ज्वायंट सेक्रेटरी के माध्यम से प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराई है, क्या उसमें ऐसा उद्वत हुआ है या क्या उसमें किसी आफिसर का नाम आया है, जो सीआईबी के मैम्बर्स थे और उसको इनफल्युएंस करते थे? जो पेस्टीसाइड्स, जिस कैमिकल को बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दी है, उसका उपयोग क्या भारत में होगा या उसे विदेश में ले जाया जाएगा और वह सिर्फ भारत में बनाया जाएगा? और, क्या वैसे कैमिकल्स बनाते वक्त वे प्रीकॉशन्स लिए गए हैं, जिससे अन्यथा वर्तमान में या आने वाले दिनों में भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना नहीं घटेगी?

श्री शरद पवार: माननीय सभापति जी, यह जो समस्या पैदा हुई है, यह जो गलत काम हुआ है, This was between 1996 and 2001. It happened during that period. The preliminary inquiry reveals that the money has been paid to one officer of the Central Insecticide Board and some money has been paid to some of the officers who come from the various States. So, when we got this information, we immediately took the decision to hand it over to the CBI, and let them investigate it. Whosoever is involved in this, they should take effective action against him.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, डॉव कैमिकल्स भारत सरकार पर अपना दबाव बना रही है कि जो लीगल लायबिलिटि या फाइनेन्सियल लायबिलिटि यूनियन कार्बाइड पर थी, भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग प्रभावित थे, उनके पुनर्वास के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए जो पैसा देना था, वह न देना पड़े। ऐसा जो यह दबाव पड़ रहा है, उसके लिए क्या आप संरक्षण करेंगे कि जो लीगल लायबिलिटि या फाइनेन्सियल लायबिलिटि है, उसको क्लीयरआप करके ही डॉव कैमिकल्स यहां अपना काम चला सके?

श्री शरद पवार: सभापति जी, यह पर्टिकुलर इश्यू regarding the Bhopal Gas incident does not come under this. यह समिति इश्यू है, तीन मोलेकुलर उन्होंने डवलप किए, इसका प्रपोजल सबमिट किया और सबमिट करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए कुछ लोगों को

उन्होंने पैसे दे दिए, ऐसी इन्फोरमेशन उन्होंने दी है। अमेरीका में यह इंफोरमेशन आने के बाद हम लोगों को पता लगा, न्यूजपैपर्स ने भी रिपोर्ट किया, तब यहां उनकी जो सबसिडरि है, उनको हमने पूछा कि इसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सेंटर के एक ऑफिसर को हमने पैसे दिए थे, जो अब सर्विस में नहीं है, वह रिटायर हो चुके हैं, यह बात सच है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वर्ष 2000 में रिटायर हो गए?

श्री शरद पवार: जी, 2000, 2001 में रिटायर हो गए। बाकी जो राज्यों में कई इंस्पेक्टर होते हैं, क्योंकि कहीं भी पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल होता है तो उसके सेम्पल लेने का काम इन लोगों का होता है और जो सेम्पल लेकर बाद में इन्फोरमेशन देते हैं कि ठीक है या नहीं, ऐसे कई लोगों को उन्होंने ब्राइब दिया। हमारे सामने इस तरह की इंफोरमेशन आई है और ऐसी बात सामने आ रही है कि इसमें सेंटर का एक ऑफीसर है, मगर स्टेट्स के कई हजार इंस्पेक्टर इसमें हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों पर इतनी डिटेल से जांच करनी पड़ेगी, जिसको करने के लिए सीबीआई ही एक प्रोपर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इस पर काम चल रहा है। जो तीन मोलेक्युलर क्लीयर करने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, जो इस तरह की इंफारमेशन आई, तो इस बारे में सर्टिफिकेशन कमेटी को हमने लिखा है कि आप इसकी फिर से जांच करो कि वे ठीक हैं या नही, इनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है या इसका कुछ असर हमारे एनवायर्नमेंट पर, लोगों पर, फसलों पर बुरा तो नहीं होगा। अगर होता है, तो इस बारे में कैन्सिल करने की बात भी आ सकती है। साथ ही साथ यह रिपोर्ट उनको दो महीने में पूरी करनी चाहिए, ऐसा आदेश भी उनको दिया है।

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is a very, very serious matter. Here is an America-based multi-national company which comes into our country and bribes our officials to get its products registered. As far as the CBI inquiry is concerned, the Minister has said that the necessary action will be taken. My question is: What about the action against the company? Are or are we not going to send a strong message to companies that come in and indulge in such corrupt practices that that is not going to be permitted in India? I would also like to inform the House that they are trying to register a product which is banned in their own country because of the effect on the children. The specific flagship product of this company called Dursban is banned in America and many developed countries bcause of the adverse effect on children.

This is a company which is bribing our officials because in the American eyes and MNCs' eyes, Indian children do not need to be protected from the adverse effect that they want to protect their own children from! My question to the hon. Ministry is: Is this company going to be blacklisted or

not by the Government of India? That is the demand. We do not need a CBI inquiry into this. Blacklist the company.

SHRI SHARAD PAWAR: After investigation, if it is proved then action will definitely be taken against the company.

MR. CHAIRMAN: Shri Ekanath Thakur.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I wanted to put the same question. Thank you.

Increasing the productivity of cereals

*424. SHRI SANTOSH BAGRODIA:†
SHRI KALRAJ MISHRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the plan of Government to increase the productivity of cereals, particularly wheat and rice; and

(b) whether Government have any plan to bring productivity to the international level for these cereals?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The National productivity of wheat is 2.62 tonnes per ha (2005-06) which is almost at par with World's average productivity of 2.66 tonnes ha (Food and Agriculture Organization, 2003). The productivity of rice in terms of paddy is 3.18 tonnes per ha (2005-06) against the World's average of 4.02 tonnes per ha (Food and Agriculture Organization, 2005).

Integrated Cereal Development Programme (ICDP)-Rice/Wheat/ Coarse Cereals) is in operation in different States and Union Territories of the country under Macro Management programme for increasing the production of cereal crops. Under this programme regionally differentiated strategy based on the resource endowments in different agro-climatic regions are adopted by the States to promote high yielding varieties and hybrids, resource conservation tehnologies like zero tillage and furrow irrigated raised bed system, Integrated Nutrient Management and

†*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Santosh Bagrodia.